

न्यायालय माननीय अध्यक्ष / सदस्य म0प्र0राजस्व म
सर्किट कैम्प भोपाल.

निगरानी प्रकरण क्रमांक- /2012-13

R-9-II/13

श्री विनायक शुक्ल
अधीनस्थ प्रि. 20-12-12
श्री भोपाल कम्प प्र
उत्सुक /
20-12-12

- 1- श्रीमती मीना फरहत पत्नि शकील मोहम्मद
 - 2- अतिका पत्नि साहिद मोहम्मद
 - 3- नसरीन बी पत्नि रासिद मोहम्मद
 - 4- फिरदोस जहाँ पत्नि शराफत मोहम्मद
- जाति मुसलमान निवासी-ग्राम बाँसखेडा
तहसील व जिला रायसेन म0प्र0.....आवेदिकागण

विरुद्ध

- 1- मध्यप्रदेश शासन
द्वारा:- कलेक्टर रायसेन म0प्र0।

- 2- श्री परमानंद आ0 मूलचंद
निवासी-ग्राम कानाखेडाकलॉ
तहसील व जिला रायसेन म0प्र0।.....अनावेदिकागण

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा-50 के अन्तर्गत निगरानी.

माननीय महोदय,
आवेदिका की ओर से विद्वान अपर कलेक्टर जिला
रायसेन द्वारा उनके प्रकरण क्रमांक-36/निग0/अपर कले./2010-11
में पारित आदेश दिनांक-29-11-2011 से असंतुष्ट एवं दुखी होकर
यह निगरानी याचिका निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत की जा रहा है।

Atulya
NF. 2/12

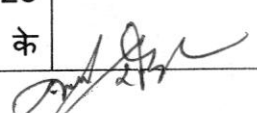
24-12-12

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 9-दो/13

जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-7-2018	<p>आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक को सुना गया । आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला रायसेन के आदेश दिनांक 26-11-2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपर कलेक्टर ने तहसील न्यायालय द्वारा नामान्तरण पंजी क्रमांक 2 दिनांक 21-5-2012 से किये गये अन्तरणों को अवैधानिक एवं विधिक प्रावधानों के विपरीत बिना सक्षम अनुमति के किया जाना पाये जाने के फलस्वरूप म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165 (7-क) के तहत शून्य घोषित किया गया है ।</p> <p>2/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-</p> <p>(1) प्रकरण क्रमांक 2/अ-19/1981-82 आदेश दिनांक 9-2-82 से प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा परमानन्द को प्रदत्त किया गया एवं प्रकरण क्रमांक 2/अ-19/86-87 पारित आदेश दिनांक 16-7-87 द्वारा उन्हें भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो गये थे, जिसके आधार पर दिनांक 19-4-89 को परमानन्द की नवीन प्रविष्टि भूमिस्वामी के रूप में दर्ज हुई ।</p> <p>(2) तहसीलदार द्वारा उपरोक्त पट्टे की जांच न करते हुए केवल वर्ष 1959 के खसरे में शासकीय भूमि दर्ज होने तथा वर्ष 1982 में परमानन्द को पट्टा प्रदान करने और वर्तमान में आवेदिका का नाम राजस्व अभिलेखों में आने का प्रतिवेदन कलेक्टर को दिया गया, जिसके आधार पर कलेक्टर ने पट्टा निरस्त करने के आदेश दिये हैं । तहसीलदार द्वारा सूक्ष्मता से जांच नहीं की गई कि परमानन्द को 1982 में पट्टा दिया गया था एवं वर्ष 1989 में उसे भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो गये थे, तत्पश्चात उसके द्वारा वर्ष 1992 में प्रश्नाधीन भूमि विजय सिंह को विक्रय की गई, जिसके आधार पर दिनांक 9-7-92 को विजय सिंह का नामान्तरण स्वीकृत हुआ एवं विजय सिंह द्वारा उक्त भूमि के.एल. ठकराल को विक्रय की थी, जिसके आधार पर उसका नाम दर्ज हो गया था और आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 2/2 रकबा 2.023 हेक्टेयर के.एल. ठकराल से विक्रय पत्र दिनांक 9-1-2006 के</p>	

माध्यम से क्रय की गई है, जिसके आधार पर राजस्व अभिलेखों में उसका नाम भी दर्ज हो गया है ।

(3) परमानन्द को वर्ष 1987 में भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त होने के उपरांत उसके द्वारा भूमि विक्रय की गई है और म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 165 (7-ख) के अंतःस्थापन के पूर्व भूमिस्वामी हो गया है तो बिना अनुज्ञा के ऐसी भूमि का विक्रय कर दिया और क्रेता का नाम नामांतरण हो गया तो ऐसी भूमि राज्य में निहित नहीं की जा सकती ।

(4) कलेक्टर द्वारा आवेदकगण के उत्तर पर बिना विचार किये एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किया है ।

(5) कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लेते समय सभी हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाया और न ही उन्हें सुनवाई का अवसर दिया । अतः पक्षकारों के कुसंयोजन के कारण भी कलेक्टर का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(6) कलेक्टर द्वारा तहसील न्यायालय अभिलेख का अवलोकन किये बगैर आदेश पारित किया है ।

(7) कलेक्टर द्वारा 28 वर्ष पश्चात समय बाह्य स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही की गई है, जबकि एक वर्ष की युक्ति युक्त समयावधि में ही स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही की जा सकती है ।

(8) स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही किसी शिकायत या अन्य शासकीय निर्देश के आधार पर नहीं की जा सकती ।

तर्कों के समर्थन में 2014 आर.एन. 196, 2004 आर.एन. 183 एवं 2013 आर.एन. 8 (उच्च न्यायालय), 2012 आर.एन. 362 2017 (1) 100, 2014 (1) 300, ए.आई.आर. 1969 एसी 1297 (सु.को.), 2000 आर.एन. 16 (उच्च न्यायालय), 1998 एम.पी. वीकली नोट 26, 2010 आर.एन. 406, 46, 2010 जे.एल.जे. 77 2006 आर.एन. 167 एवं 1998 (1) वीकली नोट्स 26 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

4/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कथित पट्टा वर्ष 1982 का है । प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय करने के लिए कलेक्टर की अनुमति आवश्यक थी, जो कि नहीं ली गई है । यह बिन्दु भी विचारणीय है कि पट्टे आबंटन का प्रकरण दर्ज नहीं होने से मूल पट्टा भी संदिग्ध है । स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय का आदेश विधि विपरीत है और ऐसे आदेश को किसी भी समय हस्तक्षेप

किया जा सकता है । अतः अपर कलेक्टर द्वारा तहसील न्यायालय के अवैधानिक एवं अनियमित आदेश को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर निरस्त करने में कोई भूल नहीं की गई है, इसलिए अपर कलेक्टर का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है । अतः आवेदकगण की ओर से लिखित तर्क में उठाये गये आधार मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं । दर्शित परिस्थिति में अपर कलेक्टर का आदेश यथावत रखते हुए निगरानी निरस्त की जाती है ।


अध्यक्ष